



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 12, 2018/फाल्गुन 21, 1939

No. 130]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 12, 2018/PHALGUNA 21, 1939

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2018

सा.का.नि. 218(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड, (समूह 'क' पद हिंदी शाखा), भर्ती नियम 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड, (समूह 'क' पद हिंदी शाखा) भर्ती (संशोधन) नियम 2018 है।

(2) ये 11 नवंबर, 2013 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड, (समूह 'क' पद हिंदी शाखा), भर्ती नियम 2013 में, आरंभिक भाग में, "भर्ती नियम, 2003" शब्दों और अक्षरों के पश्चात् "जहां तक उनका संबंध संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा), अपर विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा), उप विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा), सहायक विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा) और अधीक्षक (अनुवाद) (हिंदी शाखा) के पद से संबंधित है" अंतःस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. ए-12018/2/2010-प्रशा. 1(वि.वि.)]

खे. बिस्वाल, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

मूल नियम, अर्थात् विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड, (समूह 'क' और समूह 'ख' पद), भर्ती नियम 2003 भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) तारीख नवंबर, 10-नवंबर 16 अधिसूचना संख्या सा.का.नि. द्वारा 262, तारीख 11 नवम्बर, 2013 में प्रकाशित संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा), अपर विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा), उप विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा), सहायक विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा) अधीक्षक (अनुवाद) (हिंदी शाखा) अर्थात् विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड, (समूह 'क' हिंदी शाखा) भर्ती नियम, 2013 के पदों के लिए भर्ती नियमों को बनाते समय असावधानी पूर्वक अधिकांत हो गया था। यह प्रमाणित किया जाता है कि संशोधन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करने के द्वारा कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) संख्या सा.का.नि. सं. 262 द्वारा तारीख 11 नवंबर, 2013 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2018

G.S.R. 218(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing, (Group ‘A’ posts Hindi Branch) Recruitment Rules, 2013, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing, (Group ‘A’ posts Hindi Branch) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 11th November, 2013.

2. In the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing, (Group ‘A’ posts Hindi Branch) Recruitment Rules, 2013, in the opening portion, after the words and letters “Recruitment Rules, 2003,”, the words “in so far as they relate to the posts of Joint Secretary and Legislative Counsel (Hindi Branch), Additional Legislative Counsel (Hindi Branch), Deputy Legislative Counsel (Hindi Branch), Assistant Legislative Counsel (Hindi Branch), Superintendent (Translation) (Hindi Branch),” shall be inserted.

[F. No. A-12018/2/2010 -Admn. I (LD)]

K. BISWAL, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum

The principal rules, namely the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing (Group ‘A’ and Group ‘B’ posts) Recruitment Rules, 2003 was inadvertently superseded while making recruitment rules, for the posts of Joint Secretary and Legislative Counsel (Hindi Branch), Additional Legislative Counsel (Hindi Branch), Deputy Legislative Counsel (Hindi Branch), Assistant Legislative Counsel (Hindi Branch), Superintendent (Translation) (Hindi Branch), namely the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing, (Group ‘A’ posts Hindi Branch) Recruitment Rules, 2013, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated November, 10 – November, 16, *vide* number G.S.R. 262, dated the 11th November, 2013. It is certified that none will be adversely affected by the retrospective effect being given to the amendment rules.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 262 dated the 11th November, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2018

सा.का.नि. 219(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड (समूह ‘क’ पद प्रादेशिक भाषा) भर्ती नियम 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड, (समूह ‘क’ पद प्रादेशिक भाषा) भर्ती (संशोधन) नियम 2018 है।

(2) ये 11 नवंबर, 2013 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड, (समूह ‘क’ पद प्रादेशिक भाषा), भर्ती नियम 2013 में, आरंभिक भाग में, “भर्ती नियम, 2003” शब्दों और अक्षरों के पश्चात् “जहां तक उनका संबंध उप विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा) और सहायक विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा) के पद से संबंधित है” अंतःस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. ए-12018/2/2010-प्रशा. 1(वि.वि.)]

खे. बिस्वाल, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

मूल नियम, अर्थात् विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड, (समूह 'क' और समूह 'ख' पद), भर्ती नियम 2003 भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) तारीख नवंबर, 10-नवंबर 16 अधिसूचना संख्या सा.का.नि. द्वारा 261, तारीख 11 नवम्बर, 2013 में प्रकाशित उप विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा) और सहायक विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा) अर्थात् विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड, (समूह 'क' प्रादेशिक भाषा) भर्ती नियम, 2013 के पदों के लिए भर्ती नियमों को बनाते समय असावधानी पूर्वक अधिकांत हो गया था। यह प्रमाणित किया जाता है कि संशोधन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करने के द्वारा कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) संख्या सा.का.नि. सं. 261 द्वारा तारीख 11 नवंबर, 2013 को प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2018

G.S.R. 219(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing, (Group 'A' posts Regional Languages) Recruitment Rules, 2013, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing, (Group 'A' posts Regional Languages) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 11th November, 2013.
2. In the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing, (Group 'A' posts Regional Languages) Recruitment Rules, 2013, in the opening portion, after the words and letters "Recruitment Rules, 2003," the words "in so far as they relate to the posts of Deputy Legislative Counsel (Regional Languages) and Assistant Legislative Counsel (Regional Languages)" shall be inserted.

[F. No. A-12018/2/2010 -Admn. I (LD)]

K. BISWAL, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum

The principal rules, namely the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2003 was inadvertently superseded while making recruitment rules, for the posts of Deputy Legislative Counsel (Regional Languages) and Assistant Legislative Counsel (Regional Languages), namely the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing, (Group 'A' posts Regional Languages) Recruitment Rules, 2013, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated November, 10 – November, 16, vide number G.S.R. 261, dated the 11th November, 2013. It is certified that none will be adversely affected by the retrospective effect being given to the amendment rules.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 261 dated the 11th November, 2013.